

मुकदमों का विवरण

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से मोहर सिंह (मृत) बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य कलेक्टर और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील Nos.7504-7505)

नवंबर 07,2023

[सूर्या कान्ट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:यदि अपीलकर्ता प्रथम भाषा अपीलों में अत्यधिक देरी के बावजूद अपनी अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के अनुदान में अपने सह-ग्रामीणों के साथ समानता की मांग करने के हकदार हैं।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, **1894**-क्षतिपूर्ति-सह-ग्रामीणों के साथ समानता की मांग-पहली अपील की भाषा में **13** साल की देरी-दंड:

आयोजित किया गया:अपीलन्यायालय ्रताओं को अपनी अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के अनुदान में अपने सह-ग्रामीणों के साथ समानता की मांग न्यायालय ने का अधिकार है-प्रतिपूरक मामलों में लिंग अपील में अत्यधिक देरी, अपने आप में घातक नहीं हो सकती है क्योंकि पार्टियों के बीच अधिकारों और समानताओं को कानूनी लाभों से इनकार न्यायालय के अच्छी तरह से संतुलित किया जा सकता है, जैसे कि विलंबित अवधि के लिए ब्याज-इस प्रकार, पहली अपील (अपीलों) में देरी को इस शर्त के अधीन माफ किया जा सकता है कि अपीलन्यायालय ्रता विलंबित अवधि के लिए अनुचित लाभ प्राप्त न्यायालय ने के हकदार नहीं होंगे-इस तरह का अनुग्रह अपीलन्यायालय ्रता के पक्ष में भी दिया जा रहा है क्योंकि अन्य भूमि मालिकों के कहने पर पहली अपीलों का एक समूह अभी भी था।

842

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से मोहर सिंह (मृत) बनाम उत्तर प्रदेश कलेक्टर और ओआरएस का राज्य।

मुआवजे का हकदार @Rs.150 प्रति वर्ग कि. मी.उनकी संबंधित अधिग्रहित भूमि के लिए यार्ड-हालांकि, मुआवजे की राशि में यू/एस निर्धारित दर के अनुसार सॉलेटियम सहित वैधानिक ब्याज शामिल नहीं होगा।³⁴ संदर्भ न्यायालय यू/एस द्वारा पुरस्कार पारित होने की तारीख से अधिनियम की अवधि के लिए।¹⁸ उच्च न्यायालय -भारत का संविधान-अनुच्छेद 14 के समक्ष संबंधित पहली अपीलों के अंतिम चरण तक।[पारस 12-14 और 15]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

जितेंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य सी. ए.

No.12631/2017-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील Nos.7504-7505।

2011 के एफ. ए. No.228 और 2011 के डी. सी. ए. No.312574 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 09.03.2016 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

प्रदीप कांत, एस. डब्ल्यू. ए. कादरी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रोहित कुमार सिंह, सिमरजीत सिंह रेखी, अतुल कृष्णा, शुभम, आदित्य शर्मा, सईद कादरी, अनुराग नगर, वर्णित शर्मा, के. एस. राणा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

रवींद्र कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, बिनय कुमार दास, सुश्री प्रियंका दास, सुश्री नेहा दास, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थियों की भूमि, जो गाँव खोरा, परगना लोनी, तहसील दादरी, जिला गाजियाबाद में स्थित है, कुल एक एकड़ भूमि का हिस्सा और अंश थी, जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 4 (1) के अंतर्गत एक अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित करने का प्रस्ताव किया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों सहित केवल 337.892 एकड़ की भूमि, कुल मिलाकर, थी

844

/

[2023] 14 एस सी आर।

अधिग्रहित और पुरस्कार विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय द्वारा 01.02.1991 पर पारित किया गया था, जिसमें Rs.70 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया था।यार्ड।3. अपीलार्थियों सहित अधिकांश भूमि मालिकों ने अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत निर्देश दिए। ज्ञात दसवीं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद ने दिनांक 06.04.1998 के एक निर्णय के माध्यम से उन संदर्भों को आंशिक रूप से स्वीकार किया और Rs.106 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे को बढ़ाया।यार्ड।

4. विभिन्न भूमि मालिकों ने मुआवजे को और बढ़ाने के लिए प्रथम अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।इन अपीलों में प्रथम अपील No.491/1998 (वीर सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), प्रथम अपील No.493/1998 (मेघ सिंह और

अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) और प्रथम अपील No.477/1998 (अमर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) आदि शामिल थे।

5. हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने उचित समय के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की। अंततः उन्होंने वर्ष 2011 में पहली अपील को प्राथमिकता दी। उनकी अपीलों को सीमा द्वारा रोक दिया गया था; इसलिए, उन्होंने 12 साल और 353 दिनों की देरी के लिए माफी के लिए आवेदन किया। अपीलार्थियों द्वारा देरी को माफ करने के लिए जो आधार लिए गए थे, वे थे कि निरक्षरता और गरीबी के कारण वे न्यायालय शुल्क की व्यवस्था नहीं कर सके और उन्हें सितंबर, 2011 में अपील करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने यह याचिका भी रखी कि उसी संदर्भ पुरस्कार के खिलाफ पहली अपील उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी।

6. उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से देरी को माफ करने से इनकार कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों द्वारा की गई पहली अपील (अपीलों) को खारिज कर दिया गया है।

7. इस बीच, अन्य भूमि मालिकों द्वारा पसंद की गई पहली अपीलों के समूह पर 04.07.2016 पर निर्णय लिया गया, जिसमें उच्च न्यायालय ने Rs.130 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे को बढ़ाया। यार्ड। 04.07.2016 दिनांकित निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार है:

“19. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, दावेदार-अपीलकर्ताओं के नेतृत्व में सभी अपीलों को इस हद तक अनुज्ञात जानी चाहिए कि अपीलकर्ता सभी वैधानिक लाभों और ब्याज के साथ-साथ उनके द्वारा पहले से प्राप्त राशि के समायोजन के बाद प्रति वर्ग गज 130 रुपये का मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे। न्यायालय शुल्क में अवज्ञा 845 होगी।

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से मोहर सिंह (मृत) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कलेक्टर और ओआरएस।

फिनेल डिक्री तैयार करते समय दावेदार-अपीलार्थियों से वसूली की जाएगी। ”

8. यह भी रिकॉर्ड की बात है कि कुछ भूमि मालिक, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की दर से अभी भी असंतुष्ट होने के कारण, सी. ए. No.12631/2017 (जितेंद्र और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य) और संबंधित मामले। एक समन्वय पीठ ने दिनांकित 12.12.2017 आदेश के माध्यम से निम्नलिखित आदेश के संदर्भ में उन अपीलों को आंशिक रूप से अनुज्ञात ः

“देरी को माफ कर दिया गया।

अनुमति दी गई।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 17 मार्च, 1988 को जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण कार्यालय ने Rs.70-प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा प्रदान किया और संदर्भ न्यायालय ने इसे Rs.106-प्रति वर्ग गज तक बढ़ा दिया। विकास लागत के लिए 35 प्रतिशत की कटौती करने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल्य Rs.130-प्रति वर्ग गज था।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय में, आक्षेपित आदेशों में केवल इस पहलू के संबंध में संशोधन की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा 35 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत कटौती की जानी चाहिए। हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में 35 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत की कटौती करते हैं। इस प्रकार, मुआवजे की राशि Rs.130-प्रति वर्ग यार्ड के बजाय Rs.150-प्रति वर्ग यार्ड पर आती है। मुआवजे की राशि को वैधानिक लाभों के साथ बढ़ाकर Rs.150-प्रति वर्ग गज कर दिया गया है।

भूमि मालिकों के नेतृत्व में की जाने वाली अपीलों को उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात जाती है।
"

9. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील पहले अपने सह-भूमि मालिकों के साथ समानता चाहते हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय ने Rs.130 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया है। यार्ड, इसके बाद इस न्यायालय द्वारा Rs.150 प्रति वर्ग मीटर तक वृद्धि की गई। यार्ड। यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय को देरी को माफ कर देना चाहिए था और अपीलकर्ताओं को उनके सह-ग्रामीणों के समान व्यवहार करना चाहिए था, जिनकी अपीलें उस समय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थीं। उसी सादृश्य पर, वह इस न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किए गए उच्च मुआवजे की मांग करता है

846

/

[2023] 14 एस सी आर।

जितेंद्र और अन्य (सुप्रा) में, इसके बाद उठाए गए दूसरे विवाद के प्रति पूर्वाग्रह के बिना।

10. इसके बाद यह प्रचार किया जाता है कि संदर्भ न्यायालय Rs.106 प्रति वर्ग कि. मी. के बाजार मूल्य का आकलन करते हुए। यार्ड गाँव माकनपुर की आसपास की भूमि के लिए दिए गए मुआवजे की दर पर निर्भर था और चूंकि, उच्च न्यायालय ने बाद में गाँव माकनपुर की भूमि के लिए मुआवजे को बढ़ाकर Rs.297 प्रति वर्ग मीटर कर दिया। प्रथम अपील No.522/2009 (प्रदीप कुमार और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में 21.04.2016 पर निर्णय लिया गया, इस तरह की संशोधित दर को गाँव खोड़ा की भूमि और गाँव मकानपुर की भूमि के बीच समानता बहाल करने के लिए अपनाया जाना चाहिए। इस आधार पर, यह दावा किया जाता है कि अपीलकर्ता भी Rs.297 प्रति वर्ग कि. मी. की उच्च दर के साथ क्षतिपूर्ति के हकदार हैं। यार्ड।

11. इसके विपरीत, एन. ओ. आई. डी. ए. के विद्वान वरिष्ठ वकील का जोरदार तर्क है कि पहली अपील में लगभग 13 वर्षों की अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी हुई थी। जिन अपीलार्थियों ने इस मामले पर विचार किया कि वे संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की दर से संतुष्ट हैं, उन्हें उनकी घोर लापरवाही के कारण उच्च न्यायालय द्वारा उपयुक्त नहीं ठहराया गया है। नतीजतन, अपीलकर्ताओं ने समानता की मांग करने के अपने तथाकथित अधिकार को खो दिया, जो लालच से किए गए एक विचारशील दावे के अलावा और कुछ नहीं था। वे बताते हैं कि पहली अपील कुछ दोषों के साथ की गई थी, जिसमें अवज्ञाकारी न्यायालय शुल्क भी शामिल था और उन्होंने कभी भी इस तरह के दोषों को ठीक नहीं किया। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, निरक्षरता या गरीबी की दलील एक लंगड़ा बहाना था। न केवल यह कि अपीलकर्ता एक ऐसे क्षेत्र के निवासी हैं जो एन. सी. आर. में आता है, उन्होंने संदर्भ न्यायालय से एक अच्छी क्षतिपूर्ति राशि भी प्राप्त की थी, जो केवल गरीबी और अज्ञानता की उनकी याचिका को झुठलाता है।

12. पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन पर, हम संतुष्ट हैं कि अपीलार्थी अपनी अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के अनुदान में अपने सह-ग्रामीणों के साथ समानता की मांग करने के हकदार हैं। इस न्यायालय ने लगातार कई निर्णयों में कहा है कि प्रतिपूरक मामलों में लिंग अपील में अत्यधिक देरी, अपने आप में, घातक नहीं हो सकती है क्योंकि पार्टियों के बीच अधिकारों और समानताओं को वैधानिक लाभों से इनकार करके अच्छी तरह से संतुलित किया जा सकता है, जैसे कि विलंबित अवधि के लिए ब्याज। इस प्रकार हमारी यह सुविचारित राय है कि पहली अपील में देरी को इस शर्त के अधीन माफ किया जा सकता है कि अपीलार्थी विलंबित अवधि के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

हम 847

एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से मोहर सिंह (मृत) बनाम उत्तर प्रदेश कलेक्टर और ओआरएस का राज्य।

अपीलार्थी के पक्ष में इस तरह का अनुग्रह इस कारण से भी प्रदान करें कि अन्य भूमि मालिकों के कहने पर पहली अपीलों का एक समूह अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। उच्च न्यायालय को देर से आने वालों को संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने की तारीख से पहली अपील के अंतिम चरण तक की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत मुआवजे सहित ब्याज का लाभ देने से इनकार करना चाहिए था। 13. गाँव माकनपुर की भूमि के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दर पर बढ़े हुए मुआवजे के लिए अपीलकर्ताओं के दावे पर ध्यान देते हुए, यह देखा जा सकता है कि ऐसी याचिका भूमि मालिकों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से उठाई गई थी जब उनकी पहली अपील पर निर्णय लिया गया था। उच्च न्यायालय ने Rs.130 प्रति वर्ग किलोमीटर की कम दर पर मुआवजे का दावा करते हुए उक्त दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। गाँव खोरा की भूमि के लिए यार्ड। इस न्यायालय ने आगे की अपील में गाँव खोरा के भूमि मालिकों के दावे

को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और मुआवजे को बढ़ाकर Rs.150 प्रति वर्ग किलोमीटर कर दिया।यार्ड।दूसरे शब्दों में, गाँव खोरा और माकनपुर की अधिग्रहित भूमि के बीच समानता के दावे को इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था।हम एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं देखते हैं।नतीजतन, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं रखते हैं कि अपीलकर्ता गाँव माकनपुर के भूमि मालिकों के बराबर मुआवजे के हकदार हैं।

14. Rs.297 प्रति वर्ग कि. मी. की उच्च दर के लिए अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करने का हमारे पास एक और प्रशंसनीय कारण है।यार्ड।हमने उनकी पहली अपीलों के लिए लगभग 13 साल की देरी को माफ कर दिया है, केवल संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर समान रूप से रखे गए भूमि-मालिकों के बीच समानता के लिए।यदि अपीलकर्ताओं को उनके सह-भूमि मालिकों की तुलना में अधिक मुआवजा दिया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे समक्ष अपने उपचार को तुरंत आगे बढ़ाने में सतर्क थे, तो यह उन भूमि मालिकों के साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव का कारण बनेगा, जिनके भाग्य पर इस न्यायालय ने पहले ही मुहर लगा दी है।यह उस पर प्रीमियम देने के बराबर भी होगा, जिसे उपयुक्त रूप से अपीलार्थियों का पुराना, विलंबित और संयोग दावा कहा जा सकता है।

15. ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, अपीलों को आंशिक रूप से अनुज्ञात जाती है; अपीलकर्ताओं को Rs.150 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजे का हकदार माना जाता है। उनकी संबंधित अधिग्रहित भूमि के लिए यार्ड।हालांकि, मुआवजे की राशि में अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार, अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ न्यायालय द्वारा पुरस्कार पारित करने की तारीख से लेकर अंतिम अवधि तक की अवधि के लिए कानूनी ब्याज शामिल नहीं होगा।

848

/

[2023] 14 एस सी आर।

उच्च न्यायालय के समक्ष संबंधित पहली अपील।अपीलार्थियों को चार सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय शुल्क में अवज्ञा को पूरा करना होगा, जिसके बाद केवल बढ़े हुए मुआवजे के बकाया का भुगतान उन्हें आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

16. तदनुसार आदेश दिया।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों को आंशिक रूप से अनुज्ञात गई।

दिव्या पांडे